फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 16 प्रभात जयपुर, सोमवार 17 अगस्त, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

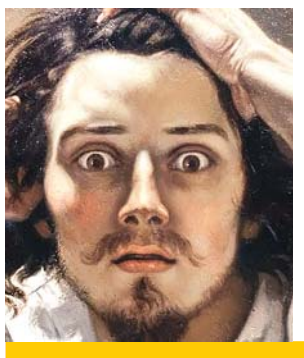

The Desperate Man (Le Désespéré)

He looks straight at us. Not away and not past us. At us. Courbet painted this early in his life before he would become the artist who would challenge French painting

The Timeless Appeal of Seersucker

Drum Beats in the Rainforest

'हाईकोर्ट "आर्बिट्रेटर" की फीस की पुनर्गणना तथा सुनवाई का कार्यक्रम तय नहीं कर सकता'

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कार्यरत रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज दीपक वर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 16 अगस्त। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले की एच सी एल और जयपुर, जोधपुर, अजमेर के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीच चल रहे भुगतान के विवाद को "आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल" (मध्यस्थता न्यायाधिकरण) एक महीने में सुनवाई करके 15 दिन में निस्तारण करे, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर करी गई है।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने मामले के तुरंत निस्तारण के साथ-साथ यह भी कहा था कि उक्त मामला 2020 से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में लंबित है जिसकी सुनवाई को मूलतः 2023 तक निपटा लेना चाहिए था, परन्तु दो बार अतिरिक्त समय दिए जाने के बावजूद मामले की सुनवाई खत्म नहीं हुई है। इसपर चिंता और नाराजगी जताते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के न्यायधीश सुनवाई में विलंब के कारण दोनों पार्टियों द्वारा दी गई फीस का एक हिस्सा लौटाये। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि बार-बार अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी अगर मध्यस्थता की प्रक्रिया खत्म नहीं हो रही है तो यह मध्यस्थता के कानून और उसके भाव को ही खत्म कर देता है और यह ट्रिब्यूनल के "आलसी और अनौपचारिक रवैये" को दर्शाता है।

- **हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में 2020 से लंबित एच सी एल व प्रदेश की सभी विद्युत वितरण निगमों के बीच 530 करोड़ के भुगतान के चल रहे विवाद को निपटाने के लिए यह फैसला दिया था कि ट्रिब्यूनल 1 महीने में सुनवाई पूर्ण करे और उसके 15 दिन के भीतर फैसला सुनाए।**
- **हालांकि अदालत ने माना था कि एच सी एल और निगमों के बीच चल रहा विवाद अत्यन्त ही पेचीदा है और इसमें 33 अलग-अलग दावे हैं, जिसे अपने आप में ही एक अलग मामले के तौर पर देखा जा सकता है।**
- **अदालत के समक्ष यह भी तथ्य प्रस्तुत था कि ट्रिब्यूनल के समक्ष 50 हजार दस्तावेज तथ्यों के तौर पर दायर करे गए थे जिसकी सुनवाई में समय लगना ही था।**

हाई कोर्ट के इस फैसले और इस टिप्पणी के खिलाफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज दीपक वर्मा, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के न्यायधीश भी है, ने चुनौती दी है।

उनकी ओर से यह याचिका वाहिब हुसैनी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है।

इस मामले के तथ्य के अनुसार एच सी एल और राजस्थान के अलग अलग विद्युत वितरण निगम के बीच विद्युत विभाग के आधारभूत ढांचे के विस्तार, विकास व सुधार करने के लिए 11 साल का अनुबंधन 2009 में किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए एच सी एल को कुल 528 करोड़ से भी अधिक का कार्य करना था जो प्रदेश के 87 अलग अलग नगरों में किया जाना था।

इस मामले में वर्ष 2020 में जब इस कार्य को पूर्ण कर भगतान की बारी आयी तो विवाद को लेकर मामला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पहुंचा था परन्तु पहले कोविड के चलते और फिर मामले की पेचीदगी को देखते हुए, कमर्शियल कोर्ट जयपुर ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सुनवाई करने की अवधि बढ़ाने के लिए समय दिया। पाठकों को बता दे कि मध्यस्थता कानून के अंतर्गत मध्यस्थता 12 महीनों में पूर्ण हो जानी चाहिए और जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में ही बढ़ाया जाता है। उक्त मामले में मध्यस्थता अगस्त 2020 में शुरू हुई थी जिसे 2023 में खत्म होना था परन्तु उसकी समय अवधि दो बार बधाई गई और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

किसानों के दिल्ली मार्च को हरियाणा ने दिल्ली सीमा पर रोका

संगरूर, 16 अगस्त। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध सहित अन्य कृषि मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेतृत्व में 51 किसानों द्वारा पैदल दिल्ली कूच करने का एक बार फिर प्रयास किया गया, लेकिन हरियाणा प्रशासन द्वारा खनौरी बार्डर सील किए जाने के कारण शाम तक भी किसान बॉर्डर पार नहीं कर पाए।

- **पुलिस के रोकने पर किसान मेन रोड पर बैठे।**

हरियाणा प्रशासन ने कंक्रीट के बेरिकेड के साथ ही बड़े-बड़े पत्थर, लोहे के बैरिकेड वैल्डिंग करके रास्ते को पुरी तरह से बंद कर दिया है। एसकेएम (गैर राजनीतिक) के प्रमुख नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में खनौरी के गुरुद्वारा साहिब से जत्था बार्डर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन बार्डर से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिसके बाद किसान वहीं मेन रोड पर बैठ गए। हरियाणा प्रशासन ने किसानों को आगे न बढ़ने की हिदायत दी, जिस पर किसानों ने पैदल आगे जाने की अनुमति मांगी।

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसान आंदोलन दौरान शुभकरण सिंह की मौत वाले स्थान की मिट्टी लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। यात्रा पूरी तरह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देश के युवा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं- मोदी

प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस पर कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ कर आगे बढ़ना होगा

नई दिल्ली, 15 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं को विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति की सबसे बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी देश का युवा होगा और इसलिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं को अवसर, संसाधन और नई तकनीक उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने 13वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़कर आगे बढ़ना होगा। देश की गति अब रुक नहीं सकती और आने वाले वर्षों में बड़े बदलाव करने होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले एक साल में एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई का विस्तार तेजी से हो रहा है और भारत के युवाओं में इस क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता है।

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच देश में 350 विश्वविद्यालय थे, जबकि पिछले 10-12 वर्ष में 650 विश्वविद्यालय जुड़े हैं। साल 2014 से पहले 400 मैडिकल कॉलेज थे, अब इनकी संख्या 850 हो गई है।**

उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है और नेशनल ड्रोन पॉलिसी तथा खेलो इंडिया पॉलिसी जैसी पहल की गई हैं। करीब 35 वर्षों तक देश में नई शिक्षा नीति नहीं थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इससे युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल के नए रास्ते खुले हैं।

प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि 2004 से 2014 के बीच देश में 350 से भी कम विश्वविद्यालय थे, जबकि पिछले 10-12 वर्षों में करीब 650 नए विश्वविद्यालय जुड़े हैं और अब इनकी संख्या करीब एक हजार तक पहुंच रही है। साल 2014 से पहले देश में करीब 400 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़ कर करीब 850 हो गई है। विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में आ रहे हैं और युवाओं को देश में रहते हुए विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री हासिल करने का अवसर मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रखने को भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया। नशा मुक्त भारत का निर्माण सभी का सामूहिक दायित्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रांची में आंदोलनकारी छात्रों ने राहुल गांधी- हेमंत सोरेन के पुतले फूंके

छात्रों की नाराज़गी है कि सीबीआई जाँच व विवादित परीक्षाओं को रद्द करने के मामलों में कोई ठोस पहल नहीं हुई

रांची, 16 अगस्त। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रविवार को 23वें दिन भी जारी रहा। सीबीआई जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर अब तक ठोस पहल नहीं होने से आंदोलनकारी छात्रों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

इसी क्रम में छात्रों ने रविवार शाम रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले फूंके। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में भी पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था।

- **छात्र नेताओं ने घोषणा की है कि 20 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।**

आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसी वजह से आंदोलनकारी अब आर-पार की लड़ाई की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं।

छात्र नेताओं ने यह भी घोषणा की है कि 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने इसमें बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने का दावा किया है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने आत्महत्या की

कोलकाता, 16 अगस्त। बीरभूम जिले के रामपुरहाट से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बंद्योपाध्याय की रविवार सुबह

- **उनके घर से सटे पार्टी कार्यालय में उनका शव फंदे से लटका मिला**
- **आशीष बंद्योपाध्याय ने शनिवार को अनेक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। घटना स्थल पर उनका सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में काम के बदले एक पैसा भी नहीं लिया।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कड़ी होड़ लगी है, यू.एन. के महासचिव के पद के लिए

वर्तमान महासचिव अंतोनियो गुटैरस का कार्यकाल आगामी 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र का अगला महासचिव बनने की दौड़ निर्णायक दौर में पहुंच गई है। सात उम्मीदवार एक ऐसे संगठन की कमान संभालने के लिए होड़ कर रहे हैं, जो युद्धों, वित्तीय संकट, नौकरशाही की सुस्ती और अपनी प्रासंगिकता को लेकर बढ़ते संदेहों से जूझ रहा है।

30 जुलाई को सुरक्षा परिषद में हुए पहले अनौपचारिक मतदान (स्ट्रॉ पोल) में कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिन्सपैन 10 समर्थन वोटों के साथ सबसे आगे रहीं। उनके बाद गुयाना की कैरोलिन रोड्रिग्स-बिरकेट को नौ और अर्जेंटीना के राफेल मारियानो ग्रॉसी को सात वोट मिले। यह मतदान बाध्यकारी नहीं था, लेकिन इससे पहली बार उम्मीदवारों की स्थिति का संकेत मिला।

- **हालांकि, सभी मान रहे हैं कि सात गंभीर उम्मीदवार हैं, पर, मजे की बात यह है कि यह माना जा रहा है कि इस बार किसी महिला को ही महासचिव बनने का सम्मान मिलेगा।**
- **और संभवतया यह महिला या तो लैटिन अमेरिका या कैरिबियन द्वीप समूह से होगी।**
- **हालांकि, केवल एक पुरुष, अर्जेंटीना के राजनयिक ग्रॉसी को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। पर, शायद इसी कारण वे अन्य देशों के व्यापक समर्थन से वंचित माने जा रहे हैं।**
- **अंततोगत्वा इस चयन को सिक्यूरिटी काउन्सिल के 15 सदस्यों का समर्थन चाहिए तथा सिक्यूरिटी काउन्सिल के पाँचों स्थाई सदस्यों के वोटों का उपयोग उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए।**

अंतोनियो गुटैरस का उत्तराधिकारी चुनने की यह दौड़ असामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। गुटैरस का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अगले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को मध्य पूर्व और यूक्रेन में संघर्षों, बढ़ते मानवीय संकटों, धन की कमी और हजारों कार्यक्रमों और बैठकों वाले इस संस्थान में बड़े बदलावों की मांगों का सामना करना होगा।

सातों उम्मीदवार मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र से हैं। इनमें चार महिलाएं हैं। इससे इस लंबे समय से चली आ रही उम्मीद को बल मिलता है कि अब इस क्षेत्र की बारी आनी चाहिए और आदर्श रूप से अगला महासचिव एक महिला होनी चाहिए।

70 वर्षीय ग्रिन्सपैन, जो कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की महासचिव रह चुकी हैं, शुरुआती दौर में सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरी हैं। अर्थशास्त्र और विकास के क्षेत्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जो वंदे मातरम् नहीं कहते, नहीं जानते, उनकी माँ कौन है?'

तिरुवनंतपुरम, 16 अगस्त। केरल विश्वविद्यालय के कुलपति मोहनन कुन्नुम्मल ने शनिवार को कहा कि जो लोग "वंदे मातरम्" नहीं कहते, वे नहीं जानते कि उनकी मां कौन है। वह मणिविला में आरएसएस के युवा सम्मेलन, संकल्प 2026 युवा संगम, को संबोधित कर रहे थे। कुन्नुम्मल ने कहा कि भारत माता ने ही बच्चों को उनके माता-पिता को सौंपा है।

- **केरल विश्वविद्यालय के उपकुलपति के बयान ने विवाद खड़ा किया।**

उन्होंने कहा, "प्रतिभाशाली बच्चे और आदर्श नागरिक बनाने की जिम्मेदारी परिवार के हर पुरुष और महिला मुखिया की है। मैं कहूंगा कि यह जिम्मेदारी परिवार की महिला मुखिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हैल्थ इंश्योरैंस पॉलिसी के अंतर्गत क्या-क्या इलाज कवर होंगे, कितना खर्च आएगा और मरीज को अंततोगत्वा कितना जेब से खर्च करना होगा'

मरीज के सामने प्रस्तुत इन दुविधाओं को खत्म करने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं, हैल्थ इंश्योरैंस के क्षेत्र में

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अगस्त। भारत का हैल्थ इंश्योरैंस सैक्टर, बड़े बदलाव की दहलीज पर नज़र आ रहा है, क्योंकि, रैगुलेटर, बीमा कंपनियां और अस्पताल, मैडिकल खर्च और बीमा कवरेज को उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शी और निश्चित बनाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं।

प्रस्तावित सुधारों में इलाज के स्टैण्डर्ड रेट, एक कॉमन हैल्थ बीमा पॉलिसी, बीमा कवरेज के लिए योग्य इलाज की एक समान लिस्ट और नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज को बड़े पैमाने पर अपनाना शामिल है। इन मुद्दों पर चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उन परिवारों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जो अस्पताल के बिल चुकाने के लिए बीमा पर निर्भर हैं।

- **रैगुलेटर्स, इंश्योरैंस कंपनियाँ, अस्पताल तथा सी.आई.आई. की संयुक्त विशेष समिति इस बारे में अपनी रिपोर्ट इस मुद्दे पर साल के अंत तक देगी।**
- **हॉस्पिटलाइज़ेशन के खर्च के अलावा, दवाईयों के दाम, जाँच-पड़ताल की कीमत, स्पैशलाइज़्ड डॉक्टरी परामर्श में भारी अंतर होता है। अतः स्टैंडर्डाइज़ेशन रेट तय करने की बात चल रही है।**
- **इन प्रस्तावों की सार्थकता इसी से सिद्ध होगी कि वो कैसे संतुलन बैठाते हैं, कंज़्यूमर (मरीज) के अधिकारों व हैल्थकेयर की लागत में।**

चर्चा से जुड़े लोगों के अनुसार, रैगुलेटर, बीमा कंपनियों, अस्पतालों और कॉन्फिडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों वाला एक पैनल इस साल के अंत तक अपनी सिफारिशें दे सकता है। इस पैनल की अध्यक्षता इंश्योरैंस रैगुलेटरी एण्ड डवलपमैंट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (आईआरडीएआई) के प्रमुख कर रहे हैं।

इन प्रस्तावों पर अभी चर्चा चल रही है और इन्हें लागू करने से पहले जरूरी रैगुलेटरी प्रोसैस से गुजरना होगा।

सुधार की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? भारत की स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था में एक बड़ी समस्या अस्पतालों की फीस और बीमा पॉलिसी की शर्तों में बहुत ज्यादा अंतर होना है। एक ही इलाज की कीमत अलग-अलग अस्पतालों में काफी अलग हो सकती है। जबकि, बीमा पॉलिसियों में कवरेज से बाहर की चीजों, वेटिंग पीरियड, कमरे के किराये की सीमा, कुछ खास खर्चों की अधिकतम सीमा और किन इलाजों को कवरेज में शामिल किया गया है, इसकी परिभाषा अलग-अलग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शेख हसीना को वापस भेजेंगे, तभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आएंगे

ढाका, 16 अगस्त। बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसी शर्त पर भारत आएंगे, जब भारत वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश वापस भेज देता है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम ने भारत के न्योते पर रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अधिकारी तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर

- **बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा से पहले शर्त रखी।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)